

मध्यप्रदेश शासन  
मुख्य सचिव कार्यालय  
भंत्रालय

भोपाल दिनांक

22-1-2014

कम/मु.स./वन.अधि. R-62/14/3-25  
प्रति.

1. समस्त संभागीय आयुक्त,  
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश

विषय-वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियाचयन समय सीमा में पूर्ण करने बाबत।

प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन क्षेत्र में उनके परम्परागत अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही जनवरी 2008 से की जा रही है, परन्तु क्रियाचयन के लगभग 6 वर्ष के अन्तराल के बाद भी वन अधिकारों के महीन दावों अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अभी भी कतिपय वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता से वंचित रह गये हैं।

2. जन संकल्प 2013 के संकल्प क्र. 7.1 "घरों से खेती कर रहे जनजाति वर्ग के कृषकों को उनके कब्जे की वन भूमि को शेष रहे पट्टे प्रदान करने हेतु विशेष अभियान/निरस्त दावों की पुनर्समीक्षा" के अनुसार जिले में सुनियोजित रूप से विशेष अभियान चलाकर शेष रहे सभी पात्र वन निवासियों को उनके कब्जे की वन भूमि के हक प्रमाण पत्र दिये जाये। अधिनियम में परिभाषित उनके परम्परागत समुदायिक अधिकारों की मान्यता दिये जाने की कार्यवाही भी की जाये, साथ ही पूर्व में निरस्त किये गये दावों की पुनर्समीक्षा की जाये।

3. निरस्त दावों के पुनरीक्षण में यह देखा जाए कि कहीं अनुचित रूप से या राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों में संबंधित वन निवासी के कब्जे का साक्ष्य उपलब्ध हात हुए भी दावदा-दार साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण तो दावा निरस्त नहीं किया गया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो विभागीय साक्ष्य को सम्मिलित करते हुये दावा मान्य करने की कार्यवाही की जाये। यह कार्यवाही हर जिले में 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व पूर्ण कर ली जाये। और मासिक प्रगति प्रतिवेदन आगामी माह से भेज दिये जाये।

4. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी वन क्षेत्र का कोई भी ग्रामवारी जानकारी के अभाव में अपने वन अधिकार का दावा प्रस्तुत करने से वंचित न रहे।

आपसे अपेक्षा है कि आप अपने संभाग एवं जिले में समय सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करायेंगे। और प्रतिमाह प्रगति प्रतिवेदन भी भेजेंगे।

(अंन्टोनी डिरा)  
मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

527  
25.1.14